MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have listened to his answer. He has clarified that...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: Machines and systems are manned by people ...*(Interruptions)*... I am not trying to defend anybody...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Why are these posts lying vacant?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different issue. That issue is not related with Mangalore incident.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, all I am saying, with great sense of respect to the entire House, is that there is no issue of trying to brush anything under the carpet. I am only stating the facts as they are, and if I do not do that, it would be doing disservice to the people, thousands of people, who are making flying for you and me as safe as possible. I am not saying that anything is not possible to be corrected. In fact, we have recently constituted a Civil Aviation Safety Advisory Council. It has met twice. I myself have been part of that Council. Irrespective of the fact that whether I am a Minister or not, I said, "No, it is important." And, we have taken people, experts from all walks of life in civil aviation to be members of that Council to advise and to guide the DGCA and the Government also in what needs to be done. If there is some scope of correction and improvement, and also the fact that if vacant posts are to be filled, so will they be. But, it's a question of technical people; it not just about a head count. It is about bringing the right headcount, and the people who can do their job effectively. I share the concerns of each and every Member here, and I also share what Venkaiahji is saying. Nobody is trying to say that all is only well. I am only stating the facts on the basis of the questions. I was answering on the issues raised by the hon. Members. I was not answering a larger debate on civil aviation sector. I was only answering and being specific to the questions raised, and I am sure that if there is any issue which further needs to be examined and corrected, you are a good friend of mine, invite me for a cup of tea, and...*(Interruptions)*... I will bring whatever changes are required.

——————

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Diversion of funds earmarked for SCs/STs to Delhi Commonwealth Games, 2010

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satish Chandra Misra, we have agreed that this whole discussion should be finished within 35-40 minutes.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमें इजाजत दी है। मान्यवर, आपने कहा कि 35 मिनट में इसे समाप्त करना है।

श्री उपसभापति: वह सबके लिए है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सभी के लिए agreement हुआ है, लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि 744.354 करोड़ रुपए का विषय 35 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा, यह हम लोग देखेंगे।

मान्यवर, 744 करोड़ से ज्यादा, लगभग 750 करोड़ रुपए, जो Special Component Plan के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तरह-तरह के कार्यक्रमों में उनके उत्थान के लिए कांग्रेस शासित दिल्ली सरकार को दिए गए थे, इस रुपए को उनके उत्थान के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। Housing and Land Rights Network को RTI के तहत information मिली है, उस information को हमने आपके सामने रखा है। उस RTI information से यह सामने निकल कर आया है कि Special Component Plan के 744.35 करोड़ रुपए, जो दलित समाज, शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यल्ड ट्राइब्स के लिए उनकी अलग-अलग स्कीम्स के लिए दिए गए थे, दिल्ली में जो 14 दिन के Commonwealth Games का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों में इस रुपए को उसमें divert कर दिया है। प्लानिंग कमीशन के जो norms हैं, प्लानिंग कमीशन की जो guidelines हैं, National Development Council की जो guidelines हैं, जिनके तहत Special Component Plan के तहत यह रुपया दिया जाता है, उसमें उनका इस्तेमाल न करके खुला उल्लंघन करते हुए इस रुपए को दलित समाज और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए न देकर इन्होंने गेम्स के लिए लगा दिया है।

मान्यवर, सरकार की जो मतगणना है, उसके अनुसार अकेले दिल्ली शहर में 2.34 मिलियन पॉपुलेशन शैड्यूल्ड क्लास की रहती है और यह रुपया दिल्ली के लिए था। दिल्ली के जो कांग्रेस शासित सरकार है, उसने दलित समाज के हित में सिविक अमेनिटीज़ बढ़ाने की जगह, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जगह, कम्यूनिटी सैंटर्स बनाने की जगह, उनको प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्राइमरी स्कूल्स बनाने की जगह, उनकी उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था करने की जगह, स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाने की जगह, दलित बच्चों की उच्च पढ़ाई की व्यवस्था की जगह उस पैसे को खेलों में लगाने का काम किया है। दलित समाज के बच्चे, हो हायर एजुकेशन ले करके आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे से पैसा निकाल करके होस्टल्स बनवाए हैं, कोचिंग की व्यवस्था की है, साथ ही अन्य और भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाए हैं, इंटरप्रेन्योर डेवलपमैंट्स का काम किया है, जिससे दलित समाज के लोग कुछ सीख करके अपनी आजीविका चला सकें, यह सब काम यहां पर भी तो हो सकता था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने ऐसे कार्यों में पैसा न लगा करके उस पैसे को खेलों में लगाने का काम किया है, यह बहुत ही शर्म की बात है। इससे कांग्रेस सरकार की मानसिकता झलकती है। कांग्रेस सरकार दलित प्रेम का * और * तो करती है, लेकिन कांस्टीट्यूशन के तहत दलितों का जो हक़ है और प्लानिंग कमिशन ने जिस रुपये को उनके लिए दिया हुआ है, उस पैसे को उस काम के लिए इस्तेमाल ने करके उनका निवाला छीनने का काम किया गया है। दिल्ली में जगह-जगह गरीब समाज के जो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत उन झोंपड़ियों को उखाड़ कर फेंक तो दिया गया लेकिन उनको दूसरी जगह कोई स्थान नहीं दिया गया। पहले उनके लिए कोई आल्टरनेटिव जगह बना दी जाती, जहां जा करके वे लोग अपने को स्थापित कर लेते, लेकिन सरकार ने यह सब न करके उनको मजबूर किया कि आप सड़कों पर रहें। सरकार ने उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया और जब वे भीख मांगने के लिए खड़े हुए तो दिल्ली पुलिस ने वहां पर भी उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। न कहीं पर उनको रहने की जगह दी जा रही है, न रुकने की जगह दी जा रही है और अब तो उनको आप भीख भी नहीं मांगने दे रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर दिल्ली में इस तरह का काम हो रहा है। सिर्फ 14 दिन के खेल के लिए यह सब किया जा रहा है। इस 14 दिन के खेल में कौन सा धन आपको मिल रहा है। जो कुछ ये कर रहे हैं, वह तो आज खुल करके सामने आ ही रहा है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जिस तरह रुपये का खुला खेल चल

*Expunged as ordered by the Chair.

रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। पूरे दिल्ली शहर के फुटपाथ, जिनमे मजबूत पत्थर लगे हुए थे, उनको उखाड़ करके, नालियों को उखाड़ करके, उस पत्थर को बेच दिया गया और उसकी जगह नया पत्थर लगाया गया, जो एक हफ्ते में ही टूट गया। दिल्ली के फुटपाथों पर जो नये पत्थर लगाए गए, आज वे जगह-जगह टूट करके किनारे पर पड़े हुए हैं। यह तो एक हफ्ते का हाल है, पता नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स तक इनकी क्या हालत होगी। इनके द्वारा जहां रुपये की इतनी लूट चल रही थी, वहां क से कम इस लूट में दलितों के लिए जो स्पैशल कंपोनैंट प्लान का रुपया था, इसको तो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था।

मान्यवर, यह 744 करोड़ रुपये की जो हम बात कर रहे हैं, यह तो खाली दिल्ली की बात है। पूरे भारत वर्ष में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिए 72,000 करोड़ रुपया स्पैशल कंपोनैंट प्लान के तहत दिया गया, जिसको अन्य विभागों में डायवर्ट कर दिया गया है, लेकिन पिछले चार वर्षों में यूपीए की केन्द्र सरकार ने यह रुपया दलितों के लिए रिलीज़ नहीं किया। प्लानिंग कमिशन के तहत उसकी स्वीकृति शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों के लिए की गई थी, लेकिन उनको वह नहीं दिया गया।

मान्यवर, जहां केन्द्र सरकार इस प्रकार का कार्य कर रही है, वहीं पर दिल्ली की कांग्रेस सरकार भी उन्हीं के पीछे चल करके इसी काम को कर रही है। अगर आप दलितों को इस देश की जनता के रूप में नहीं मानते हैं, सिर्फ वोट बैंक के रूप मानते हैं, तब बात दूसरी है। या तो सरकार यह कह दे कि हम सिर्फ उनको वोट की चीज़ ही मानते हैं और इस देश में उनका कोई हक नहीं है। जिस तरह अन्य लोग हैं, अगर उसी तरह उनका भी हक़ है तो उनका जो हक़ है, उनका जो निवाला है, उसे इस तरीके से छीना नहीं जा सकता।

आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। आप दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, यह तो खुलासा हो चुका है लेकिन उनका अपमान करने का हक आपको किसने दिया? आप किसी का सम्मान मत करिए लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। भारतवर्ष को आजार हुए 60 वर्षों से ज्यादा हो गये, लेकिन आज तक दलितों के लिए सम्मान के रूप में कुछ नहीं किया गया। आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलितों के सम्मान के लिए, बैकवर्ड्स के सम्मान के लिए, डॉ. बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम जी तथा अन्य जो गुरु हैं उन सब के सम्मान के लिए स्मारक बनाने का काम किया तो समूची कांग्रेस एक तरफ खड़ी हो गई और उसका विरोध करने लगी। कांग्रेस के महासचिव तो यहाँ तक बोले कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: यह तो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला है, ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश): यह कॉमनवेल्थ गेम्स से ही जुड़ा हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: लेकिन, यह मानसिकता दिखाती है ...**(व्यवधान)**... यह मानसिकता दिखाती है। आप लखनऊ का डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको ऐतराज़ होता है। दिल्ली में तो आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर 35-40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पानी की तरह बहा दिए ओर जब हम अपने खर्चे से कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आपको विरोध होता है। मान्यवर, यह एक ऐसी चीज है जिसमें खास तौर से जो इनफॉरमेशन मिली, उसके अनुसार इस फंड को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एन.डी.एम.सी., एम.सी.डी., स्पोर्ट्स एंड यूथ, दिल्ली जल बोर्ड, अरबन वाटर सप्लाई और अरबन डेवलपमेंट में ट्रांस्फर किया गया। एक mere denial से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी ने एक बार बीच में यह कह दिया कि हमने कोई डाइवर्जन नहीं किया है, तो इससे काम नहीं होगा। स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान के इस फंड का आपने कैसे इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया, इसका खुलासा करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस बात को लेकर हमारी आपसे यह माँग है कि उत्तर प्रदेश को छोड़ कर पूरे देश में सरकारी नौकरियों में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जो बैकलॉग बनाकर रखा हुआ है, नहीं दिया है। हर मामले में दलितों को आपने पीछे छोड़ा है, लेकिन कम-से-कम इस मामले में, जिसमें कि यह चीज़ गम्भीरतापूर्वक आपके सामने आई है, जहाँ पर आपने स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान में, चाहे वह दिल्ली का हो या वे 72 हजार करोड़ रुपए जिनको प्लानिंग कमिशन ने पूरे देश के लिए पिछले पांच वर्षों में दिया है, उसको आपने

उनके लिए क्यों नहीं रिलीज किया है? क्या उनके डेवलपमेंट की आपकी कोई चाह नहीं है? क्या आप उनके डेवलपमेंट का विरोध करते हैं? उधर से एक मामूली सा denial आएगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हम यह चाहते हैं कि इस इश्यू के लिए आप एक स्पेशल पार्लियामेंटरी कमेटी कांस्टीट्यूट करें। उसके तहत आप इसके लिए इनक्वायरी बिठाएँ और सी.ए.जी. से कहें कि वह इसमें छानबीन करे आपके सामने रिपोर्ट रखे, वह स्पेशल पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने रिपोर्ट रखे तथा इसमें जो लोग इनवॉल्व्ड हैं उनके खिलाफ सिर्फ प्रोसेक्यूशन की ही कार्रवाई नहीं हो बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन भी होना चाहिए। यह हमारी माँग है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, while associating myself with the issue raised by Mr. Satish Chandra Misra, I would like to draw the attention of the Chair as well as the House towards the information जो उन्होंने अभी बताया about Rs. 744-odd crore which was denied by the hon. Minister earlier. Here is the information. The Government of National Capital Territory of Delhi, Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, replied to the RTI applicant, Shrimati Shivani Chowdhry (ID.No.453). It says, "Kindly refer to your letter regarding Scheduled Caste sub-plan for the year 2006-2010. In this regard, kindly find enclosed herewith the desired information." This is an official information provided by the Government to the RTI applicant. In that it was said that the amount spent for the Commonwealth Games in 2006-07 was 1.97 crore; in 2007-08, it was Rs.15.57 crore; in 2008-09, it was Rs. 214.72 crore; in 2009-10, it was Rs. 288.44 crore; and in 2010-11, which is proposed, it is Rs.223.64 crore. This is an official reply given by the Ministry concerned of the Delhi State Government. This is really atrocious. It is not acceptable because this money is given as per the constitutional provision and not because of the mercy of this Government or that Government or this party or that party. संविधान के अनुसार जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत यह पैसा दिया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हो रहा है वह तो एक दूसरी कहानी है। सदन में इसकी चर्चा अलग से होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमन वेल्थ क्रिएट करना था, मगर कागज वेल्थ क्रिएट हो रहा है। वह पैसा, जो दलितों के लिए दिया गया, वह पैसा कुछ कागज के वेल्थ के निर्माण करने के लिए पूरा कर रहे हैं। उससे उनका उत्थान होना चाहिए, उनको कम्प्यूटर देना चाहिए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

उनके रहने के इलाके में sanitation की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर वह सब काम छोड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इतना पैसा, 744 करोड़ रुपये खर्च करना, जैसा मैंने कहा, atrocious and not acceptable है। This is unconstitutional that has been done by the Government. I would like the Government of India to intervene in the matter, order an enquiry and take the strongest possible action against the people concerned and also take back the money that has been diverted from the Special Component Plan (SCP). This is my request.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, हमने अपने नोटिस के साथ ...**(व्यवधान)**... लगा दिया है।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिम बंगाल): सर, मैं हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के हमारे जितने साथी हैं और नेशनल कैम्पेन फॉर दलित राइट्स के जो ग्रुप्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले पांच सालों से वे इसे फॉलो कर रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फंड है, वह कहाँ से आ रहा है। इस संदर्भ में जब पूछा गया तो दिल्ली की मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया कि हम लाग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए या विकास के लिए हमारा जो फंड है, वह एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। सर, प्लानिंग कमीशन के साथ उनकी मीटिंग मई के महीने में हुई। प्लानिंग कमीशन को भी ये सारी सूचनाएँ दी गयी थीं कि

दलितों के लिए दिल्ली सरकार के जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स हैं, उनमें से पिछले पांच सालों से कुल मिलाकर, उस समय 600 करोड़ था, इस साल को मिलाकर लगभग 744 करोड़ डायवर्ट हो गया है। सर, प्लानिंग कमीशन किसके अंडर है? प्रधान मंत्री जी खुद प्लानिंग कमीशन को देखते हैं। उनके अपने नियम हैं। उनके नियम के मुताबिक जब भी किसी स्टेट प्लान के संबंध में बातचीत की जाती है, तो उस प्लान के जो फंड्स हैं, वे किस रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं, उसकी एक मॉनिटरिंग होती है। सर, मेरे पास प्लानिंग कमीशन का वर्ष 2005 का वह सर्कुलर है, जिसके तहत उन्होंने तमाम स्टेट्स को यह हिदायत दी थी कि दलितों के लिए जो फंड्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग कमेटी है। उसके लिए प्लानिंग कमीशन में भी एक अलग कमेटी है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि non-earmarking of funds under the SCP and TSP may result in non-approval of plans of the States and Union Territories. This is the circular of the Planning Commission. Now, under the very nose of the Planning Commission, Sir, यहाँ यह दिल्ली सरकार चल रही है। इसमें multiplicity of authorities है। कहाँ से कया फंड आ रहा है, उसका कोई चेकअप नहीं है। इसलिए दिल्ली के अदंर आज यह खुलेआम हुआ है कि दलितों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनका जो पैसा है, उस पैसे को लूटा गया है। हमारे साथियों ने भी कुछ मिसाल बतायी हैं।

सर, मैं इस चार्ट को देख कर इतनी हैरान थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विलायत की महारानी के नाम एक बेटन होता है, उसके लिए उनको और कहीं से पैसा नहीं मिला, लेकिन दलितों के लिए जो पैसा है, उनकी बस्तियों के विकास के लिए जो पैसा है, उस पैसे में से उस रानी के बेटन के नाम पर 10 करोड़ रुपये खर्च हुए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि मेरे साथी ने बहुत सही कहा कि अत्याचार के शब्द को हम लोग हिंसा के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यह आर्थिक अत्याचार है कि संवैधानिक प्रावधान और अधिकार को आप लूटवेल्थ गेम्स के नाम पर छीन रहे हैं, सर, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, यह लूटवेल्थ है। उसके जो दो और पहलू हैं उसके बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ। एक तो यह कि आपने विकास का पैसा लूटा। दूसरी बात यह है कि ये मजदूर कौन हैं जो कांस्ट्रैक्स वर्कर्स के रूप में आज दिल्ली की सड़कों पर 14-14 घंटे काम कर रहे हैं? वे कौन हैं? हमें मालूम है। हमने उनसे बातचीत की है। दिल्ली में जो कांट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वह दलित है, वह scheduled castes है, वह scheduled tribes है। दिल्ली का न्यूनतम वेतन 203 रुपये है और उनको 100 रुपया भी नहीं मिल रहा है।

उनको over time करना पड़ रहा है। एक तरु तो आपने विकास का पैसा लूटा और दूसरी तरफ आप उनका श्रम लूट रहे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: शोषण, शोषण।

श्रीमती वृंदा कारत: श्रम लूटने का मतलब शोषण होता है। तीसरी बात यह है कि Today, in Delhi, the Bombay Anti-Beggary Act is in operation. Anti-beggary का मतलब है कि भिखारियों के खिलाफ मुंबई का जो कानून है, आज वह दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखा कि दूर-दूर इलाके से, जहां गांव में इतनी भारी संकट है, लोग शहर में आते हैं। यहां उनके साथ यह आलम है कि उनको दूर भगाया जा रहा है। बहुत सारी बस्तियां हैं, जहां Scheduled caste के लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़कर उनको भगाया जा रहा है इसलिए पैसा, श्रम और घर के जो अधिकार हैं, इन तीनों में दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह तो दिल्ली सरकार का दायित्व था, लेकिन इसके साथ-साथ योजना आयोग की तरफ से कोताही हुई है, भेदभाव दिखा है। अगर किसी बड़ी कंपनी के लिए एक पैसा इधर-उधर होगा, तो योजना आयोग सरकारों को दस नोटिस भेज देगा, लेकिन दलितों का पैसा लूटा जा रहा है, इस पर योजना आयोग क्यों मौन है? आज यह सवाल है।

सर, मेरी दो मांगें हैं, पहली मांग यह है कि जो 744 करोड़ रुपए हैं, वे ब्याज समेत पूरे, दलितों के विकास के लिए, वापस दिए जाएं और दूसरी मांग यह है कि यह जो component plan है, इस समय इसके लिए executive order है, इसके लिए कानूनी रूप चाहिए। इसका सांविधानिक रूप चाहिए। आज कोई सरकार executive order का इधर-उधर कर सकती है, इसलिए इसको संविधान में जोड़ा जाए। तीसरी बात यह है कि इसमें जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।

श्री जनार्दन द्विवेदी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभापति जी, मुझे बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें कहनी है। सतीश चन्द्र मिश्र जी ने, एम वेंकैया नायडु जी ने और वृंदा कारत जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं उनकी गंभीरता को समझता हूं। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इन प्रश्नों के उत्तर दे।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके साथ और सवाल नहीं जोड़े जाएं। सतीश चन्द्र मिश्र जी अगर उत्तर प्रदेश पर या किसी और मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग समय और स्थान निकल सकता है। इसलिए उसको इसके साथ न जोड़ा जाए। वृंदा जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ, उन्होंने बातें जिस ढंग से कहीं हैं, वे बहुत प्रभावशाली हैं। भौतिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, कुछ मासिक अत्याचार भी होते हैं, इसके लिए कई श्रेणियां निकल सकती हैं, उन पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। वेंकैया नायडू जी ने इसको, अपने को इसी मुद्दे तक सीमित रखा है, मुझे खुशी है कि उन्होंने और बहुत सारे सवाल नहीं उठाए। इसी तरह से दलितों के लिए किसने क्या किया है, गरीबों के लिए किसने क्या किया है, अगर इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजनाओं में जाना है, तो उस पर भी अलग से बहस हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों को छोड़कर जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, उनका जवाब सरकार दे। धन्यवाद।

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश): हम लोग इसका बराबर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपको इसमें क्या आपत्ति है ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपको तो welcome करना चाहिए ...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश): सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बाप बैठिए ...**(व्यवधान)**... उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है ...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहा है कि डिसकस करेंगे ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश दास गुप्ता: सर, आप उन पर चर्चा कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**... आपने 744 करोड़ के बारे में कुछ कहा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इसमें उन्होंने कौन-सी controversial बात कही है ...**(व्यवधान)**...

श्री ब्रजेश पाठक: अगर आप माननीय सदस्य के अनुरोध को स्वीकार करते हैं, तो आप व्यवस्था कीजिए, तब बहस होगी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: जो नियम है, उसके तहत करेंगे ...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री जुगुल किशोर: मान्यवर, यह ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए... यह क्या बात है? आप जब चाहे उठकर खड़े जो जाते हैं? आप बैठिए प्लीज़...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this subject. Despite the left, right, centre differences, the House today has taken up

this issue for discussion as one. It shows the concern everybody has got towards the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. What we are discussing today is just an iceberg and the issue is larger. The question of Special Component Plan for the Scheduled Castes and the Tribal Sub Plan are larger issues, and I am having the information that several State Governments even today do not earmark funds for Special Component Plan or Tribal Sub Plan. More than 24 Central Departments under the Union Government do not have separate allocation for these Plans and they consider this fund is indivisible. Having said that, I must point out, Sir, the diversion of money meant for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Commonwealth Games is unpardonable. It is betrayal of the Constitutional responsibilities of an elected popular Government, whether it is a State Government or the Central Government. And, I think, this has to be treated as an offence; as an offence against the very spirit of the Constitution, and the Government claims it is the Government of *aam aadmi!* Whatever it is doing is against the *aam aadmi.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: I am saying it is not just an atrocity. It is very serious modern day atrocity, grabbing the fair share and due share of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the nation's wealth which they create, and this is a great offence by the elected Governments in the name of democracy, and we cannot tolerate such things to continue. Sir, lastly, the Commonwealth Games should have been a pride of the nation, but it is becoming a big shame. And it is becoming a big scam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing the Commonwealth Games.

SHRI D. RAJA: That is why I am not discussing, but the Government should take note of it. The diversion of money is done in the name of Commonwealth Games. The Commonwealth Games, we all should feel proud of it, but it is becoming a shame; it is becoming a scam. What is the answer of the Government?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: ...*(Interruptions)*... It is connected. That is why I am raising this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; there are so many things connected. ...*(Interruptions)*... I am here to regulate the House, not you.

SHRI D. RAJA: Sir, I understand the constraint of time. So, I would like to conclude by saying this. This is a very serious offence. It can happen in Delhi, and tomorrow it can happen in other States. That is why it is high time the Central Government will have to intervene and set right the things. As the previous speaker's demand, the money should be given back, and the Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub Plan must be treated as Plans meant for welfare of these people under the guidelines of the Planning Commission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to remind hon. Members that this is only confined to diversion of funds to Commonwealth Games. No other issues should be raised.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, मैं एक मिनट में ही खत्म कर रहा हूं। सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर पैसे का diversion हुआ है, तो इसकी proper enquiry होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sabir Ali. Only on diversion of funds. I will not allow any other issue.

श्री साबिर अली (बिहार): सर, मैं सिर्फ एक मिनट में खत्म कर दूंगा लेकिन यह उससे connected है।

श्री उपसभापति: connect मत करिए।

श्री साबिर अली: सर, अभी लोगों ने अपनी बात कही, जो पैसे का diversion हुआ है, इसकी जांची होनी चाहिए।*

श्री उपसभापति: यह चर्चा यहां नहीं आएगी। ...**(व्यवधान)**... यह चर्चा यहां नहीं आएगी। ...**(व्यवधान)**... वह नहीं आएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: *

श्री उपसभापति: दलितों का विषय यहां नहीं है, यहां diversion का विषय है।...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: उसकी चर्चा तो करते नहीं हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री महेन्द्र मोहन।...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: *

श्री उपसभापति: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।...**(व्यवधान)**... Unconnected issue will not go. आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश दास गुप्ता: आप गलत बात मत कहिए, सही बात रखिए।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sabir Ali Sahab, only that matter goes on record which is connected with the subject. ***...(Interruptions)...*** आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। मैं आपको बुलाता हूं।...**(व्यवधान)**... You have to speak only on the diversion of funds, no other issue. ***...(Interruptions)...*** We are not discussing Dalit issue, we are not discussing Uttar Pradesh, we are not discussing the country. ***...(Interruptions)...*** No question of Uttar Pradesh. ***...(Interruptions)...*** Okay, okay, your time is over. Nothing will go on record. ***...(Interruptions)...***

श्री उपसभापति: महेन्द्र मोहन जी। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। उनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... साबिर अली जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): हम बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: हमें बोलने नहीं दिया गया।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैंने आपको बोलने दिया।...**(व्यवधान)**... आपको बोलने दिया था।...**(व्यवधान)**... अब आप प्लीज़ बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

3.00 p.m.

श्री साबिर अली: सर, एक मिनट बोलने दीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**... It is not a a full-fledged discussion, it is a limited discussion allowed by the Chair as Zero Hour. So, please confine yourself only to diversion of funds to Commonwealth Games.

श्री महेन्द्र मोहन: उपसभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है जिसमें सारी जानकारी आरटीआई के अंतर्गत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाई गयी है कि 744 करोड़ रुपया शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था, उनके उत्थान के लिए था, उनके जीवन को सही बनाने के लिए था, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए था, उनकी शिक्षा के लिए था। उस रुपए को कॉमन वेल्थ गेम्स के ऊपर बर्बाद किया गया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। सर, प्लानिंग कमीशन यहीं बैठा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लानिंग कमीशन का 2005 का जो circular है, specific है कि इस प्रकार के पैसे को कभी भी divert नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी यह कार्य किया गया है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत इस बात की जानकारी दी गयी है कि इस पैसे को इस प्रकार से divert किया गया है। इससे अधिक गंभीर विषय यह है कि कई सालों से एससी, एसटी का रुपया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इसे वे गंभीरता से लेंगे।...**(व्यवधान)**...

श्री महेन्द्र मोहन: इसके implementation को देखा जाना चाहिए। एक तरफ हम लोग यह कहते हैं कि एससी, एसटी का उद्धार नहीं हो रहा है, उनको बहुत कमियों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रहीं हैं और दूसरी ओर रुपया पड़ा रहता है और उस रुपए का उपयोग नहीं किया जाता है। जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी और सरकार ऐसा कार्य न कर सके। धन्यवाद।

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (Nominated): Sir, thank you very much. I just want to share two things with the House. The circulars which have been quoted of the Planning Commission, from time to time, and the guidelines issued by the Planning Commission to the Central Government, as well as, to the State Governments, I was privileged to be a party to drafting all these circulars on behalf of the Planning Commission. It is not a question confined to the Planning Commission alone. The diversion of Rs.744 crores by any measure, by any criteria is indefensible. It is not a problem only of the Planning Commission. In the 52nd meeting of the National Development Council which all the hon. Chief Ministers of different States attended the meeting, the decision was of the National Development Council that the funds earmarked for the Special component Plan and the Tribal Sub-Plan are not lapsable and non-divertible. In view of this, it is a serious matter and the Government owes a serious explanation for this. Thank you.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, the hon.

Member, Shri Satish Chandra Misra, has raised a serious issue. I have got a notice for Calling Attention just half an hour ago. You have, in your wisdom, allowed this to be raised as a Zero Hour matter. It is a very serious matter. I think that some information has been obtained through the RTI. I will apprise the Government about the matter being raised. I think that the Government will come back with full information and exact details of what is happening very shortly.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: मान्यवर कब तक देंगे, बतला दें? आप दो दिन में लाएंगे, तीन दिन में लाएंगे, यह सदन को बतला दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They want to know if it will be within a week. ***...(Interruptions)...***

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: The Government will come back very soon. ***...(Interruptions)...***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is saying that the Government will come back very soon. We have to believe the Minister. ***...(Interruptions)...***

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: The matter concerns a State Government. We will have to get the information from the State Government. I know it is a very serious matter. I will come back on it. I assure the House that there is no question of any diversion of money which is meant for the SC and ST. We have to get correct information. I will come back to the House on this issue as soon as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He may come back even before one week.

श्री सतीश चन्द्र मिश्र: आप यह सदन को बतला दें।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, 'as soon as' can be before monsoon or it can be after the monsoon. I agree with the Minister because he has to get in touch with the Delhi Government. It takes time. At least he can give the commitment that it will be done in the coming week.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: I accept the suggestion given by the hon. Member, Shri Venkaiah Naiduji.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2009.

GOVERNMENT BILLS

The Industrial Disputes (Amendent) Bill, 2009

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted .